MODVAT Benefits

1409. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that MODVAT benefits have not been fully passed on to the consumers in many cases;

(b) what is the reasons of net revenue loss to Government, while MODVAT should have been revenue neutral;

(c) whether such anomalies are desirable at the initial stage and whether corrective measure have been taken; if so, what are the details thereof; and

(d) whether Government have received representations to the effect that introduction of MODVAT in certain industries has been counter productive and if so, whether the same will be withdrawn?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) to (d) In 1986 Budget, in order to ensure revenue neutrality, the introduction of MODVAT was accompanied by an increase in the duty on the final products to balance the set off which was being given of the duty paid on inputs. In 1987 Budget, having regard to the nature of the products, the duty rates of the final product were not increased except in a few items The question whether the MODVAT benefit was fully passed on to the consumers or not would thus depend upon the nature of the commodities.

The magnitude of availment of MODVAT credit in the year 1987-88 has been more than in 1986-87. While extending the MODVAT Scheme to additional Chapters of Central Excise Tariff in 1987 Budget, the rates of excise duty in respect of some items were not increased, having regard to the nature of products. Further, in regard to the inputs manufactured by the small scale sector, duty is realised at a concessional rate but credit is allowed at full effective rate on a notional basis. The wider coverage of goods in respect of which the notional credit is being availed of has also contributed to the increased utilisation of MODVAT.

Duty rates in respect of a few items were raised in 1987 Budget, where it was found that the credit availed of was larger than what was initially estimated. In 1988 Budget also, excise duty rates on certain items, such as paints based on synthetic polymers, trailers and coated textiles, have been increased as a part of MODVAT corrections of duty rates.

A few representations have been received to the effect that the MODVAT Scheme has posed certain problems. However, as the industry has found the MODVAT Scheme generally beneficial, there is no proposal at present to withdraw the Scheme.

प्रधान मंत्री कार्यालय में हिंदी का प्रचार

1410. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री कार्यालय में राजभाषा हिंदी की घोर उपेक्षा होती है, क्योंकि वहां पर कोई हिंदी सलाहकार समिति अथवा राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है और वहां संसद सदस्यों के हिंदी में लिखे हुए पत्रों को पढ़ने वाला कोई नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वहां से मुद्दा-दर-मुद्दा जवाब कभी नहीं मिलता और

(ख) यदि हां, तो हिंदी भाषा की उन्नति के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ना मणि पाणि ग्रही) : (क) और (ख) जी नहीं, यह कहना सही नहीं है । प्रधान मंत्री कार्यालय किसी मंत्रालय अथवा विभाग से भिन्न है । यह एक ऐसा कार्यालय है जो प्रधान मंत्री को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है । हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के लिये बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में मंत्रालयों/विभागों में ही हिन्दी सलाहकार समितियां गठित करने

के आदेश हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही इस कार्यालय में हिंदी सलाहकार समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। इस कार्यालय में एक पूरा हिंदी एकक है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये जारी निर्देशों के कार्यान्वयन का काम इस कार्यालय के एक उच्चस्तरीय अधिकारी को सौंपा गया है। कार्यालय में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिये जायें, और जहां कहीं आवश्यक हो, उनका हिन्दी में मदवार उत्तर दिया जाता है।

Case against Syed Abdullah Bukhari

1411. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Delhi Police had booked a case against Syed Abdullah Bukhari for his reported inflammatory speech on 30th March, 1987 at the Boat Club, New Delhi;

(b) if so, what follow-up action was taken and with what results;

(c) whether it is a fact that the Kerala High Court had directed the Delhi Police to produce the Imam in the Court on December 18 last to face a charge of contempt, but the Delhi Police did not care for the High Court's directive; and

(d) what is Government's policy in this regard and what action has been taken in the matter so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Kerala High Court had sent a bailable warrant of arrest directing the Commissioner of Police, Delhi, to arrest and produce Syed Abdullah Bukhari before that High Court on or before 18-12-1987. The warrant was returned unexecuted as Syed Abdullah Bukhari was away in Pakistan at that time.

(d) A watch is maintained and legal action is taken if any one propagates communal hatred.

आतंकवादियों/उग्रवादियों द्वारा मारे गए लोग

1412. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आतंकवादियों/उग्रवादियों ने पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और कितनों को घायल किया ; और

(ख) सरकार ने उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन

1413. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिंदी अनुभाग की फाइलों को छोड कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिंदी में काम किया जा रहा है ;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है ; और

(घ) मंत्रालय में हिंदी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?